

6 महीने में बदल जाएगा पुराना इनकम टैक्स कानून!

जल्द पूरा होगा आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा का काम

नई दिल्ली, 22 अगस्त. अनेक वाले दिनों में इनकम टैक्स से जुड़े नियम-कानून और आसान हो जाएंगे। क्योंकि, सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा कर रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि इनकम टैक्स एकट, 1961 के रिच्यू का काम 6 महीनों की निर्धारित समयसीमा में पूरा कर लिया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा था कि देश के प्रत्यक्ष कर कानून को सरल बनाने के लिए



इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने इस काम को छह महीनों में पूरा करने की बात कही थी। आयकर विभाग का नियंत्रण अधिनियम, 1961 की व्यापक करने वाले सीबीडीटी के प्रमुख

अग्रवाल ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, "हमारे पास एक महत्वपूर्ण काम है जो आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा का तय समय में पूरा कर लिया जाएगा।

मुक्तमेवाजी को कम करना और करदाताओं को कर निश्चिता प्रदान करना है।"

कर कानून को सरल बनाने का काम शुरू- अग्रवाल ने कहा कि सीबीडीटी ने इसके लिए मिशन अंदाज में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह काम चौतीस पूर्ण और परिवर्तनकारी होने के बावजूद निर्धारित समयसीमा में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आयकर विभाग के 165 वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आश्वस्त किया कि समीक्षा को तय समय में पूरा कर दिया गया।

ITR की नई व्यवस्था लोगों को पसंद

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई व्यवस्था लोगों को पसंद आ रही है और करोबर 72 प्रतिशत करदाताओं ने इसे दुना है। रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक 58.5 लाख लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न जमा किए। उन्होंने कहा कि अब तक सपर्क-रहित व्यवस्था के तहत कुल 6.76 लाख आयकर अंकलन पूरे किए गए हैं, जबकि जुलाई तक 2.83 लाख अपीलों को अंतिम रूप दिया गया।



निवेशकों को मिला डबल रिटर्न

निवेशकों के लिए जारी से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने की तैयारी में है तो बड़ा झटका लगा सकता है। सरकार के सूत्रों से इस बारे में बड़ी जानकारी मिली है। निवेश के लिए महंगा और जटिल इंस्ट्रमेंट होने की वजह से सरकार अब आगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं रख सकती है। हालांकि, ये जानकारी सूत्रों से मिली है और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। पेपर गोल्ड के तौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार ने साल 2015 में लांच किया था। उस दौरान विदेशों से भारत में सोने का आयत तेजी से बढ़ रहा था।

बंद हो सकती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड

सरकार पेपर गोल्ड स्कीम को जारी रखने पर नहीं कर रही विचार

नई दिल्ली, 22 अगस्त। अगर आप भविष्य में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने की तैयारी में है तो बड़ा झटका लगा सकता है। सरकार के सूत्रों से इस बारे में बड़ी जानकारी मिली है। निवेश के लिए महंगा और जटिल इंस्ट्रमेंट होने की वजह से सरकार अब आगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं रख सकती है। हालांकि, ये जानकारी सूत्रों से मिली है और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। पेपर गोल्ड के तौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार ने साल 2015 में लांच किया था। उस दौरान विदेशों से भारत में सोने का आयत तेजी से बढ़ रहा था।

कुल 67 द्वांच जारी, 4 मैचेंडर हुए- भारत सरकार की ओर से भारतीय रिवर्व बैंक इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैनेज करता है। इस स्कीम के लांच होने से अब तक कुल 67 द्वांच में निवेशों ने 72,274 करोड़ निवेश किए हैं। इनमें से 4 द्वांच पूरी तरह से मैचेंडर भी हो चुके हैं। इस बॉन्ड को खरीदने वाले निवेशकों को बोर्ड रीडेप्सन के जरिए पेसे वापस चुकाए जा चुके हैं।

भारत का डायमंड एक्सपोर्ट घटा

प्रीमियर-2024 में सोने के आभूषणों का दबदबा



अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते सूत्र में कई डायमंड फैसिलिटीज़ ने इस महीने अपने कर्मचारियों के 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया था। जीर्जीपीसी ने कहा है कि वैश्विक आसानी के बाद उपभोक्ता मांग में कमी के कारण जुलाई में कुल रन और आधुनिक एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 23.28 प्रतिशत रहने की अनुमान है, जो पिछली छह तिमाहीयों में सबसे कम है। रेटिंग एंजेंसी इका ने बृहस्पतिवार को यह बताया।

इका का समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीर्जीपी) की दर के 6.8 प्रतिशत रहने की अनुमान है। इसी महीने की शुरुआत में एपर्सीआरटीसी और डीडिंगर रेलवे कैरियर्स के लिए डीएमआरसी मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल करने वाले यात्री भी नमों भारत ट्रेन टिकट भी खरीद सकते हैं। एकोकृत क्यूआर-कोडेड टिकटिंग के लिए हाथ मिलाया है। इस समझौते का फायदा यह है कि टिकट के लिए एक बार एक बार दो यात्राएं को जानकारी देता है। इस समझौते का फायदा यह है कि यात्री एक ही बुकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दिल्ली-एनसीआर में दिल्ली-मेट्रो और नमों भारत दोनों दोनों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं।

इस एकांकण के साथ, RRTS कनेक्ट एप्लिकेशन के साथ, नियर्मान के लिए एक बार एक बार दोनों दोनों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं।

भारत का डायमंड एक्सपोर्ट घटा

प्रीमियर-2024 में सोने के आभूषणों का दबदबा

अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते सूत्र में कई डायमंड फैसिलिटीज़ ने इस महीने अपने कर्मचारियों के 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया था। जीर्जीपीसी ने कहा है कि वैश्विक आसानी के बाद उपभोक्ता मांग में कमी के कारण जुलाई में कुल रन और आधुनिक एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 23.28 प्रतिशत की अनुमान है, जो पिछली छह तिमाहीयों में सबसे कम है। रेटिंग एंजेंसी इका ने बृहस्पतिवार को यह बताया।

जीर्जीपीसी के चेयरमैन विपुल शाह के अनुसार, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इका का समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीर्जीपी) की दर के 6.8 प्रतिशत रहने की अनुमान है, जो पिछली छह तिमाहीयों में सबसे कम है। रेटिंग एंजेंसी इका ने बृहस्पतिवार को यह बताया।

जीर्जीपीसी के चेयरमैन विपुल शाह के अनुसार, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इका का समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीर्जीपी) की दर के 6.8 प्रतिशत रहने की अनुमान है, जो पिछली छह तिमाहीयों में सबसे कम है। रेटिंग एंजेंसी इका ने बृहस्पतिवार को यह बताया।

जीर्जीपीसी के चेयरमैन विपुल शाह के अनुसार, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इका का समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीर्जीपी) की दर के 6.8 प्रतिशत रहने की अनुमान है, जो पिछली छह तिमाहीयों में सबसे कम है। रेटिंग एंजेंसी इका ने बृहस्पतिवार को यह बताया।

जीर्जीपीसी के चेयरमैन विपुल शाह के अनुसार, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इका का समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीर्जीपी) की दर के 6.8 प्रतिशत रहने की अनुमान है, जो पिछली छह तिमाहीयों में सबसे कम है। रेटिंग एंजेंसी इका ने बृहस्पतिवार को यह बताया।

जीर्जीपीसी के चेयरमैन विपुल शाह के अनुसार, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इका का समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीर्जीपी) की दर के 6.8 प्रतिशत रहने की अनुमान है, जो पिछली छह तिमाहीयों में सबसे कम है। रेटिंग एंजेंसी इका ने बृहस्पतिवार को यह बताया।

जीर्जीपीसी के चेयरमैन विपुल शाह के अनुसार, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इका का समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीर्जीपी) की दर के 6.8 प्रतिशत रहने की अनुमान है, जो पिछली छह तिमाहीयों में सबसे कम है। रेटिंग एंजेंसी इका ने बृहस्पतिवार को यह बताया।

जीर्जीपीसी के चेयरमैन विपुल शाह के अनुसार, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इका का समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीर्जीपी) की दर के 6.8 प्रतिशत रहने की अनुमान है, जो पिछली छह तिमाहीयों में सबसे कम है। रेटिंग एंजेंसी इका ने बृहस्पतिवार को यह बताया।

जीर्जीपीसी के चेयरमैन विपुल शाह के अनुसार, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में भू-राजन